

राज्य की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लि. की खानों, स्मेल्टरों  
से निकालने वाले पारे पर प्रदूषण विभाग की चुप्पी!!!

जबकि जांच के दौरान प्रदूषण विभाग ने माना कि कंपनी के चंदेरिया स्मेल्टर में  
सल्फ्यूरिक एसिड में छोड़ा जा रहा है जानलेवा पारा!!!

भाग-5

कंपनी के चंदेरिया स्मेल्टर के अधिकारी के अनुसार,  
पहले आगुचा स्थित खान से  
आता था अयस्क, जिसमें पारे की मात्रा ना के बराबर!!!  
अब आता है राजसमंद स्थित सिंदसर खुर्द खान से अयस्क,  
जिसमें से हो रहा पारे का पूर्ण शोधन!!!

जबकि चंदेरिया(चित्तौड़गढ़)स्मेल्टर से निकलने वाले,  
एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से स्थानीय निवासियों  
के खेत और जीवन दोनों संकट में!!!

कंपनी के दरीबा(राजसमंद) और देबारी(उदयपुर) स्थित स्मेल्टरों में,  
पारे के शोधन की जांच के मामले में,  
कंपनी और प्रदूषण विभाग दोनों को देते नहीं बन रहा जवाब!!!

**हिंदुस्तान ज़िंक के खनन से राजस्थान में मच रहा हाहाकार!!!**

जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से,  
कंपनी की खानों और स्मेल्टरों से हो रहा,

वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग!!!

मानव जीवन, खेत खलिहान, नदी तालाब, पेड़ पौधे सब खतरे में!!!

ज़िंक अयस्क में रहने वाला पारा हर रूप में खतरनाक!!!

व्यापक जांच और शोध की जरूरत!!!

एनजीटी लगा चुका है कंपनी की आगुचा माइंस(भीलवाडा)  
पर 25 करोड़ की क्षति-पूर्ति तत्काल जमा करवाने के आदेश!!!

एनजीटी का आदेश और स्थानीय निवासियों की परेशानियाँ,  
हमारे दावों की कर रहे पुष्टि!!!

**हिंदुस्तान जिंक लि. की रामपुरा आगुचा(भीलवाडा),सिंदेसर खुर्द(राजसमंद)जावर(उदयपुर)राजपुरा दरीबा (राजसमंद) और कायड(अजमेर)मे है खाने,साथ ही चंदेरिया(चित्तौड़गढ़),दरीबा(राजसमंद) और देवारी (उदयपुर)मे है स्मेल्टर प्लांट**

हिंदुस्तान जिंक लि द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी जिंक लेड का खनन करने वाली विश्व की दूसरी, जिंक लेड का स्मेल्टिंग करने में विश्व की चौथी एवं चाँदी के उत्पादन में विश्व की छठी कंपनी है। भारत की जिंक इंडस्ट्री में इसका शेयर 77% है।

राजस्थान में कंपनी की रामपुरा आगुचा(भीलवाडा),सिंदेसर खुर्द(राजसमंद)जावर(उदयपुर)राजपुरा दरीबा(राजसमंद) और कायड(अजमेर)मे जिंक,लेड की खाने है। साथ ही चंदेरिया(चित्तौड़गढ़),दरीबा(राजसमंद) और देवारी(उदयपुर)मे कंपनी के स्मेल्टर प्लांट है।

**राज्य की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लि. की खानों,स्मेल्टरों से निकल रहा जानलेवा पारा|कंपनी के स्मेल्टरों में नहीं किया जा रहा पारे का शोधन**

पिछली रिपोर्ट में हमारे द्वारा खुलासा किया गया था कि हिंदुस्तान जिंक लि. की खानों रामपुरा आगुचा(भीलवाडा),सिंदेसर खुर्द(राजसमंद)जावर(उदयपुर)राजपुरा दरीबा(राजसमंद) और कायड(अजमेर) से निकलने वाले जिंक अयस्क में पाये जाने वाले पारे का शोधन उसके स्मेल्टरों; दरीबा-राजसमंद और देवारी-उदयपुर में नहीं किए जाने से यह जिंक अयस्क के एक अन्य उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड में घुल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कंपनी द्वारा अपने चंदेरिया-चित्तौड़गढ़ स्थित स्मेल्टर में वर्ष 2019 में Mercury Removal System

लगाने की बात प्रदूषण विभाग को सौंपी गयी अपनी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में स्वीकार की गयी थी, जिसका सीधा अर्थ था कि इससे पूर्व इस स्मेल्टर में भी पारे को अलग नहीं किया जा रहा था। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वर्तमान में इस प्लांट से पारे को अलग करने की प्रक्रिया अपनायी भी जा रही है या नहीं।

आपको ज्ञात हो कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग डिटर्जेंट, सीमेंट, धातु उद्योग, केमिकल/डाई फैक्ट्रियों और खाद और उर्वरक बनाने के कारखानों में किया जाता है। कंपनी द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड से पारे को अलग नहीं करने से वर्षों से पारा डिटर्जेंट, सीमेंट, धातु उद्योग, केमिकल/डाई, खाद और उर्वरक के जरिये हमारे वातावरण और शरीर में जहर बन कर घुल रहा है और कई खतरनाक बीमारियाँ पैदा कर रहा है।

जवाब दो!!!  
सरकार  
www.jawabdosarkar.com  
देश का पहला जवाबदारी पोर्टल

इसके पल्ला - 2021ak/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest संपादन: 1 सितम्बर 2021

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-2

**आखिर कहाँ जा रहा है, राज्य की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लि. की खानों से निकलने वाला पारा??**  
**पारे के खतरे से राज्य सरकार बनी मुकदर्शक!!!**  
**राजस्थान में खान, सीमेंट रासायनिक खाद और उर्वरक इंडस्ट्री में पारे की धमक!!!**  
**क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू की गयी मीनामाटा संधि से रुकती मानव जीवन में पारे की घुसपैठ?**

पता:-S1, झारखंड अपार्टमेंट, सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151 पृष्ठ 1  
\*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं संपादन प्रकृत (IT Act 2000) के तहत उचित है। सर्वाधिकार ©www.jawabdosarkar.com



## हिंदुस्तान की 'मर्करी' पर विवाद

**कंपनी के स्मेल्टरों द्वारा पारे का शोधन नहीं करने के मामले में प्रदूषण विभाग की लीपापोती!!**

**चंदेरिया स्थित स्मेल्टर प्लांट के निरीक्षण में दिखी फौरी कार्यवाही**

इस मामले में फ्रस्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रदूषण विभाग की नींद खुली और मामले की जांच के आदेश दिये। जिस पर दिनांक 10/09/2021 को प्रदूषण विभाग, चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्लांट के अधिकारी द्वारा बताया गया कि चंदेरिया स्मेल्टर में पहले भीलवाड़ा स्थित रामपुरा आगुचा माइंस से लाये गए जिंक अयस्क का शोधन किया जाता था, जिसमें पारे और इसके अन्य अवयवों की मात्रा ना के बराबर (10 PPM से भी कम) होने से इस स्मेल्टर में पारे और इसके अन्य अवयवों का शोधन नहीं किया जाता था। वर्तमान में चंदेरिया स्मेल्टर में राजसमंद स्थित सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले अतिरिक्त जिंक अयस्क का शोधन किया जा रहा है, जिसमें पारे और इसके अन्य अवयवों की मात्रा 40-50 PPM के आस-आस है, जिसके लिए कंपनी द्वारा दिनांक 14/10/2020 को प्रस्तुत ईसी नवीनीकरण के दौरान हवाला दिया गया है। जिंक अयस्क से पारा मरक्यूरस क्लोराइड यानि केलोमल के रूप में प्राप्त होता है। कंपनी द्वारा दिनांक 14/10/2020 को प्रस्तुत ईसी नवीनीकरण में पारे और इसके अन्य अवयवों का उत्पादन 0.0 MTPA बताया गया है, जबकि पहले इनका उत्पादन 22.0 MTPA था। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि पारे और इसके अवयवों को अब हेजर्डियस प्रोडक्ट नहीं मानकर बाय-प्रॉडक्ट माना जाता है। क्यूंकी पारे की कीमत 40-50 लाख प्रति टन है। कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार स्मेल्टर में तीन मर्करी रेमूवल टावर क्रमशः हाईड्रो-1, हाईड्रो-2 और पायरो में वर्ष 2005, 2006 और वर्ष 1990 से ही लगे हुए हैं लेकिन वर्ष 2020 तक इन तीनों टावरों में नगण्य रूप में केलोमल का उत्पादन किया जाता था। कंपनी द्वारा दिनांक 14/10/2020 को प्रस्तुत ईसी नवीनीकरण के बाद से 6 MT केलोमल का उत्पादन किया जा रहा है।

**कंपनी के जवाब पर प्रदूषण विभाग ने मांगे दस्तावेज़, साथ ही माना कि पारे का शोधन नहीं करने के दौरान यह प्रवाहित कर दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में।**

कंपनी द्वारा दिये गए जवाब पर प्रदूषण विभाग द्वारा स्मेल्टर के प्रभारी से उनके दावों के पुष्टि के संदर्भ में निम्न दस्तावेज़ मांगे गए हैं जो कि निम्न हैं:-

1. रामपुरा आगुचा और सिंदेसर खुर्द से आने वाले जिंक अयस्क में पारे की उपलब्धता से संबंधित विगत 5 सालों के आंकड़े एवं संबंधित रिपोर्ट।
2. जिंक अयस्क से प्राप्त होने वाले सभी उत्पादों, सह-उत्पादों, हेजर्डियस वेस्ट मेटेरियल से संबंधित विगत 5 सालों के सम्पूर्ण आंकड़े, साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड में पारे की मौजूदगी से संबंधित 5 सालों के आंकड़े।
3. प्रत्येक माइंस से आने वाले जिंक अयस्क के अनुसार चंदेरिया स्मेल्टर में खपत होने वाले जिंक अयस्क की सालाना रिपोर्ट (किस खान से कितना अयस्क हर साल लाया गया)।
4. कंपनी के एसिड प्लांट में से निकलने वाले पारे की 5 सालों की एनेलेसिस रिपोर्ट।
5. विगत 5 सालों की सालाना केमिकल कंजमप्शन रिपोर्ट।

विभाग द्वारा उक्त रिपोर्टों को शीघ्र मुख्यालय स्तर पर जमा करने की सलाह भर दी गयी। जबकि अब तक तो ऐसे गंभीर मामले में कंपनी को शो कॉज़ नोटिस जारी किए जा चुकने थे।

इन दस्तावेज़ों के साथ विभाग के अधिकारी द्वारा यह भी चौंकने वाला खुलासा किया गया कि चंदेरिया स्मेल्टर को जारी नवीन पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 14/10/2020 पूर्व में जारी कनसेंट टू ओपरेट और कनसेंट टू स्टेबलिश में स्मेल्टर के तीनों एसिड प्लांटों में से पारे के शोधन हेतु कोई निर्धारित मानक तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में कैसे तय होगा कि कंपनी द्वारा किन शर्तों/मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है?

7. No prescribed standard for mercury is defined in stack of Acid plant of all three plant (Sulphuric Acid Production) in Environmental Clearance dated 14.10.2020 and also in consent to establish and operate issued by the Board.

12. In case the mercury not trapped in Mercury Removal Towers concentration of mercury shall be increased in their byproduct Sulphuric Acid. They are maintaining mercury concentration in sulphuric acid less than 2.0 PPM. Also they are regularly analyzing the mercury in sulphuric acid to maintain concentration of the same.

साथ ही इस बात का भी खुलासा किया कि यदि स्मेल्टर के मर्करी रेमुवल टावरो में से पारा अलग नहीं होता तो इसे सल्फ्यूरिक एसिड में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ ही यह भी दावा किया कि कंपनी द्वारा स्मेल्टर से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड में पारे की मात्रा को 2.0 PPM से कम रखा जाता है।

विभाग के गैरजिम्मेदाराना बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान में प्रदूषण विभाग के पास ऐसा कोई मेकेनिज़्म नहीं है जिससे कंपनी द्वारा उसके स्मेल्टरों में पारे के शोधन या सल्फ्यूरिक एसिड में पारे की मात्रा तय करने पर कोई निगरानी रखी जा सके। विभाग द्वारा स्वयं कोई जांच नहीं करवाकर मात्र कंपनी से ही कागजी कार्यवाही पूरी करवायी जा रही है।

## कंपनी के दरीबा(राजसमंद) और देबारी(उदयपुर) स्थित स्मेल्टरो मे पारे के शोधन के सवाल पर कंपनी और प्रदूषण विभाग दोनों की चुप्पी।

हमारे द्वारा प्रदूषण विभाग द्वारा कंपनी के तीनों स्मेल्टरों (चंदेरिया,दरीबा और देबारी) मे पारे के शोधन की जांच करवाने का अनुरोध किया गया था लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण विभाग के चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा कंपनी के चंदेरिया स्थित स्मेल्टर की जांच करने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ही साहस किया गया।इस मामले मे विभाग के दो अन्य जिलो राजसमंद और उदयपुर और मुख्यालय के अधिकारी मुंह पर ताला लगाए बैठे हुए हैं।उदयपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री विनय कट्टा द्वारा अपने पत्र मे यह बताया गया कि उनके द्वारा कंपनी के देबारी स्थित स्मेल्टर का निरीक्षण दिनांक 11/09/2022 को किया गया था।लेकिन निरीक्षण मे क्या कमियाँ पायी गयी इसका खुलासा उनके द्वारा नहीं किया गया और ना ही सूचना के अधिकार के तहत अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी। प्रदूषण विभाग के राजसमंद स्थित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा तो उनके अधिकार क्षेत्र मे स्थित कंपनी के दरीबा स्मेल्टर मे,इस मामले से संबन्धित किसी जांच का हवाला नहीं दिया गया और ना ही सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी उपलब्ध करवाई।इतना ही नहीं इस मामले मे प्रदूषण विभाग का मुख्यालय भी मूक दर्शक बना हुआ है और मात्र चिट्ठियाँ लेने देने का काम कर रहा है।

## हिंदुस्तान ज़िंक सल्फयूरिक एसिड का बड़ा उत्पादक,सल्फयूरिक एसिड मे घुल कर हम तक पहुँच रहा है घातक पारा।

हिंदुस्तान ज़िंक लि की अधिकृत वैबसाइट के अनुसार कंपनी के दरीबा स्थित प्लांट से 0.6 मिलयन चंदेरिया प्लांट से 0.6 मिलयन एवं देबारी प्लांट से 0.3 मिलयन टन सल्फयूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है इस प्रकार 1.5 मिलयन टन अर्थात 15 लाख टन सल्फयूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है।जिसको वाणिज्यिक उपयोग हेतु सीमेंट,केमिकल,खाद एवं उर्वरक आदि कारखानो को बेच दिया जाता है।

**क्षेत्रीय कार्यालय**  
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
एफ-470, सूतीसीआई सवन के पार, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादरी, उदयपुर 313001  
Email: rpscud@rajppur@gmail.com Website: www.environment.rajasthan.gov.in

राप्रनिम/क्षे.का./उदयपुर/आरटीआई/2020-21/1177-  
सविस्तर दिनांक: 02.12.2021

श्री ज्ञानेश कुमार C/O जवाब दो सरकार,  
पता :- एस-1 सेकण्ड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट,  
सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग,  
खातीपुरा, जयपुर (राज.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना की अपूर्ति बाबत।

सन्दर्भ :- (1) आपका आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2021, इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 08.11.2021।  
(2) क्षेत्रीय कार्यालय, राप्रनिम, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक राप्रनिम/क्षे.का.चित्तौड़.  
/सामान्य-03/21-22/949-951 दिनांक 01.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में सूचित है कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि, निकट ग्राम देबारी, जिला-उदयपुर का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.09.2021 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.09.2021, मण्डल मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर भिजवाया जा चुका है। अग्रिम कार्यवाही मण्डल मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा अपेक्षित है।

भवदीय  
विनय कट्टा  
लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-  
1. राज्य लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सूचनाार्थ सादर प्रेषित है।  
लोक सूचना अधिकारी

**क्षेत्रीय कार्यालय**  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
कलालवाटी, राजनगर, जिला राजसमन्द-313324

क्रमांक:क.रा.राप्रनिम/राजसमंद/आर.टी.आई./2021/85 दिनांक- 11-11-2021  
लोक सूचना अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
ज य पु र

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री ज्ञानेश कुमार जयपुर द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मांग कर्ता श्री ज्ञानेश कुमार C/O जवाब दो सरकार S-1 सेकण्ड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट सगतसिंह मोड जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा जयपुरद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रप्रस्तुत किया गया है।  
प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना मण्डल मुख्यालय से सम्बन्धित होने से मूल आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाता है। मूल पोस्टल आर्डर कार्यालय में सुरक्षित है।  
सर्वमूल-मूल आवेदन पत्र

भवदीय  
लोक सूचना अधिकारी  
साराप्रनिम राजसमंद

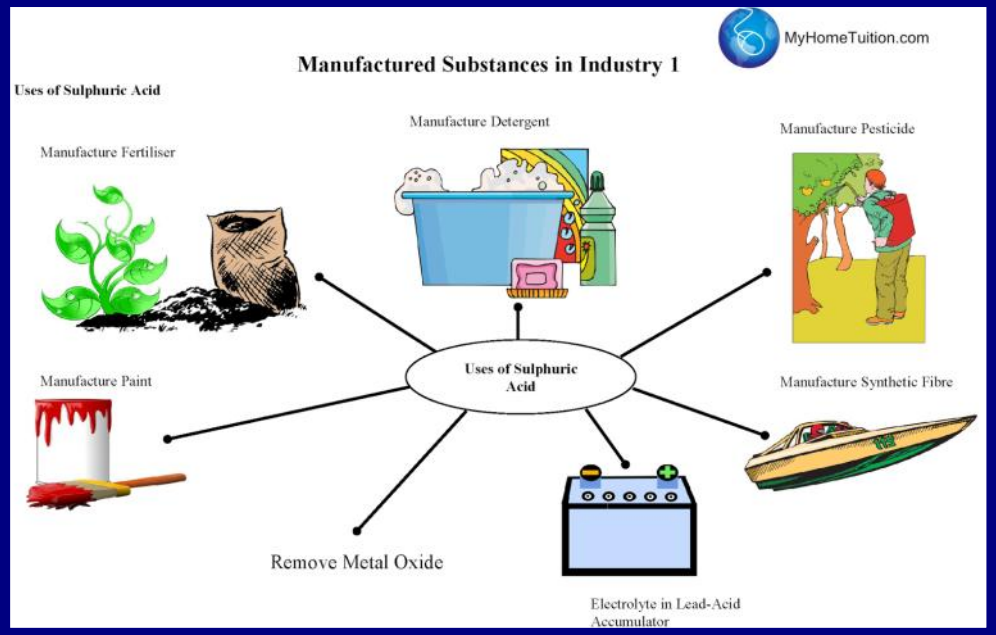
प्रतिलिपि:-  
श्री ज्ञानेश कुमार C/O जवाब दो सरकार S-1 सेकण्ड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट सगतसिंह मोड जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा जयपुर को सूचनाार्थ प्रेषित है।  
लोक सूचना अधिकारी  
साराप्रनिम राजसमंद

सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग डिटर्जेंट, सीमेंट, धातु उद्योग, केमिकल/डाई फैक्ट्रियों और खाद और उर्वरक बनाने के कारखानों में किया जाता है। यदि उचित समय पर सल्फ्यूरिक एसिड से पारे को अलग नहीं किया जाए तो यह विभिन्न उत्पादों, खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे वातावरण और शरीर में जहर बन कर घुल रहा है। यदि आज

तक के हिंदुस्तान जिंक के कुल उत्पादन का ब्यौरा निकाला जाए तो उस हिसाब से सैंकड़ों टन पारा हमारे आस पास के वातावरण में फैल चुका है और आगे भी फ़ैल रहा है।

## चंदेरिया(चित्तौड़गढ़)स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से स्थानीय निवासियों के खेत और जीवन दोनों संकट में!!!

एक तरफ जहां हिंदुस्तान जिंक लि यह दावा कर रहा है कि उसके चंदेरिया स्थित स्मेल्टर में मर्करी रिमुवल सिस्टम लगा दिया गया है और पारे को केलोमल के रूप में अलग किया जा रहा है, वही प्रदूषण विभाग के अधिकारी यह रिपोर्ट दे रहे हैं कि कभी कभी प्लांट में पारे की शोधन प्रक्रिया सुचारु नहीं होने से यह सल्फ्यूरिक एसिड में मिल रहा है। इसी बीच प्रदूषण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुछ दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है कि स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से स्थानीय निवासियों के खेत और स्थानीय जन जीवन दोनों संकट में हैं। ऐसे ही मामले में आई एक शिकायत पर प्रदूषण विभाग द्वारा बताया गया कि जिंक फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसों से चित्तौड़गढ़ के गाँव पुठोली के 129 प्रभावित किसानों एवं गाँव मूंगा का खेड़ा के 210 प्रभावित किसानों को 1182520/- राशि मुआवजे के रूप में देने की अनुशंसा की गयी थी।



### हिंदुस्तान जिंक से फैल रहा प्रदूषण

## BREAKING NEWS

st  
इंडिया  
राजस्थान

UPDATE 05/02/2021

चित्तौड़ में अब हिन्दुस्तान जिंक प्रबंधन के कारनामों का बढ़ता दायरा !

प्राणी और फसल के बाद अब पशुओं पर भी जिंक प्लांट का कहर !, बेड़च नदी में मगरमच्छ सहित हजारों मछलियों की मौत, वन्यजीव प्रेमियों ने लगाया जिंक प्लांट से कैमिकल युक्त पानी छोड़ने का आरोप, और इसी कैमिकल युक्त दूषित नदी में हो रही मछलियों की भी मौत, मगरमच्छ को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, किया जमकर प्रदर्शन, बड़ा सवाल आखिर क्यों मूकदर्शक बना हुआ है प्रशासन ?, 8 दिन पहले ग्रामीणों ने जताई थी आशंका और आज हो गई हकीकत, चित्तौड़गढ़ के पुठोली में स्थित है वेदांता समूह का हिन्दुस्तान जिंक प्लांट, हिन्दुस्तान जिंक लेड स्मेल्टर प्लांट से कैमिकल युक्त दूषित पानी निकलने का आरोप, क्या अब सरकार कराएगी हिन्दुस्तान जिंक प्रबंधन के कारनामों की जांच ?



ई मेल- ro.chittorgarh@gmail.com

01472-294158

क्षेत्रीय कार्यालय  
राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,  
एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/रा.प्र.नि.म./क्षे.का चित्तौड़/ 2021-22/342-343

दिनांक: 02-07-2021

प्रभारी अधिकारी (HOGM)  
रा.प्र.नि.म.  
जयपुर

विषय:-हिन्दुस्तान जिंक द्वारा छोड़े गये एसिड युक्त पानी से किसानों के खेत  
खराब होने से मुआवजा दिलवाने बाबत शिकायत।  
सन्दर्भ:- मण्डल मुख्यालय पत्र क्रमांक एफ-19(7)/रा.प्र.नि.म./वी.टी.आर.  
शिकायत/आर.ओ. चित्तौड़/3323-3324 दिनांक: 07.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त शिकायत तथा कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के संवध में तथा समस्त विभागों की संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मण्डल मुख्यालय जयपुर द्वारा पत्रांक F-Tech/RPCB/HOGM/(M-87)/UID-263/1168-1173 दिनांक 17.02.2021 (प्रति संलग्न-1) के द्वारा इकाई को निर्देशित किया जा चुका है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी मुआवजे का संधारण किया जाए उसे जमा करवाये जाए। इसके अतिरिक्त कृषि फॉर्म की दशा सुधारने हेतु ऑर्गेनिक खाद तथा जिप्सम जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपलब्ध करवाया जाए। इस संवध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पत्रांक क्रमांक/राजस्व/12-12(23)2021/480 दिनांक 17.03.2021 (प्रति संलग्न-2) के द्वारा मुआवजा तय करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अतः यह प्रकरण जिला प्रशासन स्तर पर ही लम्बित है, तथा मण्डल मुख्यालय द्वारा पालना हेतु इकाई को निर्देशित किया जा चुका है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय  
02 (शरद सक्सेना)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
राप्रनिम चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:-

1 प्रभारी अधिकारी (पी.सी.वी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

02 क्षेत्रीय अधिकारी  
राप्रनिम चित्तौड़गढ़



ई मेल- rochittorgarh@gmail.com

01472-255077

230  
22



क्षेत्रीय कार्यालय  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,  
एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

D: No. 693-694

दिनांक: 02-09-21

प्रभारी अधिकारी (पी.सी.वी)  
रा.प्र.नि.म.  
जयपुर।

विषय:-जिंक फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस से फसल खराब व अन्य नुकसान का मुआवजा दिलवाने का शिकायत।

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक.एफ-19(7)/रा.प्र.नि.म./वी.टी.आर.शिकायत/आर.ओ. चित्तौड़/104-105 दिनांक: 16.07.2021 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि माननीय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक 361 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा उद्योग मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, गाँव- पुठौली, चित्तौड़गढ़ के संवत्त से निकली गैस से फसल खराब के संबंध में घटना की जाँच हेतु संयुक्त विभागीय दल का गठन किया गया जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. चित्तौड़गढ़, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ तथा वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं वायुमल, चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया गया। उक्त दल द्वारा दिनांक 30.12.2020 को उक्त इकाई का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न) के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उद्योग को दिनांक 30.12.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (प्रति संलग्न)। उक्त रिपोर्ट के आधार पर इकाई को यह भी निर्देश दिये गये कि इस घटना से प्रभावित कृषकों को उचित मुआवजा सम्यन्धित विभाग के आकलन के अनुसार दिया जावे। कार्यालय तहसीलदार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 21.01.2021 (प्रति संलग्न) के अनुसार कृषि विभाग व राजस्व विभाग द्वारा प्रभावित किसानों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें ग्राम पुठौली के 129 प्रभावित कृषकों एवं ग्राम मुँगा का खेड़ा के 210 प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि रुपये 1182520/- देने की अनुशंसा की गई।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-प्रभारी अधिकारी (HOGM) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

भयदीय

(महावीर मेहता)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

## एनजीटी लगा चुका है कंपनी की आगुचा माइंस(भीलवाडा)पर 25 करोड़ की क्षति-पूर्ति तत्काल जमा करवाने के आदेश!!!

पिछले माह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हिंदुस्तान जिंक लि पर 25 करोड़ की क्षति-पूर्ति तत्काल जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा के यहा जमा करवाने और तीन सदस्यीय कमिटी का गठन कर,इलाके की भूमि और जल को हुए नुकसान का आकलन कर उसे पुनर्स्थापित करने की योजना बनाने के आदेश जारी किए थे।आदेश के अनुसार, इस कमिटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और भीलवाडा के जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे।इस मामले में दर्ज याचिका में कहा गया था कि भीलवाडा के आगुचा क्षेत्र में करीब 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में कंपनी की खाने है,जो लगातार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही है।इन खानों में कंपनी की और से भूमिगत ब्लास्टिंग की जाती है,जिससे इलाके के ग्रामीणों को पेयजल में प्रदूषण की

समस्या के अलावा दमा और चर्म रोग की समस्या भी हो रही है।साथ ही घरों और खेतों में धूल के कण भर जाते हैं।खानों से जहरीला पानी छोड़ा जाता है।

## NGT IMPOSES ₹25 CR PENALTY ON HZL FOR FLOUTING ENVIRONMENTAL NORMS

Nirmal Tiwari

**Jaipur:** The National Green Tribunal (NGT) has imposed a fine of Rs 25 crore on Hindustan Zinc Limited for violating environmental norms in Bhilwara.

At the same time, the NGT also ordered to constitute a three-member committee to assess the damage caused to



land and water in the area and to make a plan for its restoration. The panel will also assess the damage caused

to people's health and livestock in the area and will work for their improvement. A bench headed by Justice

Adarsh Kumar Goyal issued directions. He instructed HZL to deposit fine amount to DM, Bhilwara within three months. The bench ordered formation of panel, which will include representatives of CPCB, RPCB & DM, Bhilwara. Panel was directed to file a compliance report by April 30, 2023.

### एनजीटी का आदेश: पर्यावरण प्रदूषण फैलाने पर...

# हिंदुस्तान जिंक को देनी होगी 25 करोड़ की क्षतिपूर्ति

पत्रिका ब्यूरो  
patrika.com

नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान के भीलवाडा में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंदुस्तान जिंक को तीन महीने के अंदर यह क्षतिपूर्ति राशि भीलवाडा के जिला मजिस्ट्रेट के यहां जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनजीटी ने तीन सदस्यीय कमिटी का गठन कर इलाके की भूमि और जल को हुए

नुकसान का आकलन कर उसे पुनर्स्थापित करने की योजना बनाने के आदेश भी दिए हैं। यह कमिटी इलाके के लोगों और उनके पशुओं के स्वास्थ्य को हुए नुकसान का आकलन कर उनमें सुधार के लिए काम करेगा। इस कमिटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भीलवाडा के जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। एनजीटी ने कमिटी को निर्देश दिया कि उसके आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल 2023 तक दाखिल करें। याचिका भीलवाडा जिले के तहसील हर्द के अगुचा, रामपुरा, बारतिया, कोटरी, भोजरस, बारला, हर्दा,

### याचिका में ये कहा...

याचिका में कहा गया है कि इलाके में करीब 12 सौ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हिंदुस्तान जिंक की खानें हैं, जो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती हैं। इन खानों में कंपनी की ओर से भूमिगत ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे इलाके के ग्रामीणों को पेयजल में

भेरुखेड़ा और कोठिया पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने दायर की थी। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2020 को एनजीटी ने भीलवाडा के जिला क्लक्टर और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त जांच कमिटी का गठन किया था, जिसका हिंदुस्तान जिंक ने विरोध

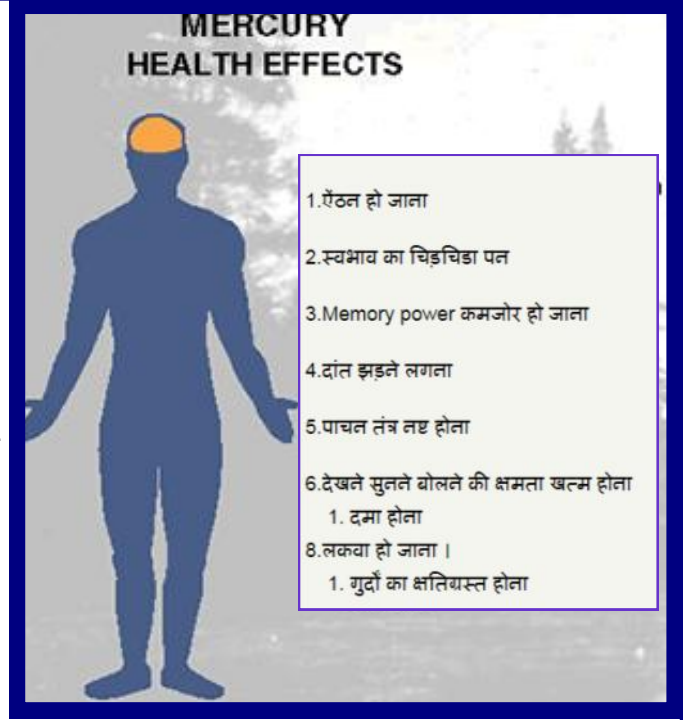
प्रदूषण की समस्या के अलावा दमा और चर्म रोग की समस्या हो रही है। साथ ही घरों और खेतों में धूल के कण भर जाते हैं। खानों से जहरीला पानी छोड़ा जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने इसे अधिसूचित इलाका घोषित कर दिया है।

किया। एनजीटी ने दूसरी कमिटी बनाई व इलाके में हुए नुकसान का आकलन करने को कहा। कमिटी ने 7 सितंबर 2021 को रिपोर्ट सौंपी जिसमें पाया कि जहरीले पानी व भूमिगत ब्लास्टिंग से उड़द-मूंग की दालों का उत्पादन गत 2 वर्षों में काफी घटा है।

## एनजीटी का आदेश और स्थानीय निवासियों की परेशानियाँ, पारे की भयावहता की कर रहे पुष्टि!!!

पारा एक भारी धातु है लेकिन सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहां बना रहता है। यह हवा, पानी, जमीन और जीव-जंतुओं में घुल जाता है। इंसान तक पहुंचने पर यह घातक असर दिखाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, "इंसान की सेहत के लिए पारा बहुत ही जहरीला है, गर्भ में पल रहे भ्रूण और बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है।" सांस के जरिए इंसानी शरीर में घुसने पर पारा तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता और प्राण घातक साबित हो सकता है। यूनेप के मुताबिक बीते एक दशक में 260 टन जहरीला पारा जमीन से बहता हुआ नदियों और झीलों में पहुंच चुका है। समुद्र की ऊपरी की 100 मीटर की तह पर बीते 10 साल में पारे की मात्रा दोगुनी हो चुकी है।

शायद यही कारण है कि यह चाहे खानो से निकलने वाली धूल में हो या फिर पानी में घुला हुआ है या फिर हवा में वाष्पीकृत हो यह हर रूप में कंपनी की खानो और स्मेल्टरों के आस-पास के सैंकड़ों गांवों-कस्बों और शहरों की आबोहवा और जल जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। इतना ही नहीं यह सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा डिटर्जेंट, सीमेंट, धातु उद्योग, केमिकल/ डाई, पेंट, खाद, उर्वरक और अन्य सामग्रियों के जरिये खाद्य श्रृंखला से होता हुआ, इन स्थानों से कोसों दूर बैठे लाखों-करोड़ों मनुष्यों के जीवन में प्रवेश कर चुका है और गुमनाम मौतों, बीमारियों का कारण बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कड़ी कार्यवाही नहीं कर कंपनी की तूती बजा रहे हैं।



### स्वामी सानंद न होते तो NGT के लिये शायद अब भी राज ही रहता सोनभद्र का जहरीला पारा

जानिये ग्रासिम इंडस्ट्री की फैक्ट्री पर जुर्माने और जहरीले पारे की पूरी कहानी।

By: रफतउद्दीन फरीद

Published: 28 Jul 2019, 03:55 PM IST Sonbhadra, Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

**सोनभद्र** - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री पर जो एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, यह संभव हो सका गंगा के लिये अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले प्रो. जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद की वजह से। स्वामी सानंद ने ही चार साल पहले इलाके में पारे के खतरनाक स्तर पर भंडारण के बारे में एनजीटी की कोर कमेटी को जानकारी दी थी। उसी के बाद आयी रिपोर्ट पर एनजीटी ने ग्रासिम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री पर 1 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। जुर्माना सोनभद्र की दुद्वी तहसील के रेनुकूट में स्थित फैक्ट्री में बाई-प्रॉडक्ट के तौर पर निकलने वाले पारे का भारी मात्रा में स्टॉक जमा करने के लिए लगाया गया है। जुर्माना एनजीटी पास जमा होगा, जो इस धनराशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में नष्ट हुए पर्यावरण को पुनर्जीवित करने में करेगा।

8/16/2021

Home > Business

### NGT orders inspection of Parle Agro Private Ltd's unit in UP

The tribunal directed the industrial unit to furnish complete set of papers to the CPCB and UPPCB.

By PTI

NEW DELHI: The National Green Tribunal has directed the departments concerned to conduct an inspection of beverage maker Parle Agro Private Ltd's unit in Uttar Pradesh to ascertain whether the industry is releasing mercury beyond the permissible limit.

## पारे के संबंध में एनजीटी द्वारा ग्रेसीम और पारले कंपनियों के विरुद्ध दिये गए निर्णय

## जवाब मांगते सवाल?

1. क्या प्रदूषण विभाग द्वारा अपने स्तर पर रामपुरा आगुचा और सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले जिंक अयस्क में पारे की उपलब्धता की जांच करवाई गयी है या फिर कंपनी के दावों को ही सही मान लिया गया है?
2. कंपनी के अनुसार उसके द्वारा सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले अतिरिक्त जिंक अयस्क के शोधन हेतु चंदेरिया स्मेल्टर के विस्तार हेतु वर्ष 2020 में नवीन पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया था, कंपनी के इस कथन के अनुसार सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले बाकी जिंक अयस्क का शोधन किस प्लांट में किया जा रहा है? क्या उस प्लांट में 40-50 PPM वाले जिंक अयस्क से पारे का शोधन किया जा रहा है?
3. चंदेरिया प्लांट के निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट्स, आंकड़ों को क्या कंपनी द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है? जिंक अयस्क से पारे के शोधन हेतु निर्धारित मानक क्या है?
4. पर्यावरण विभाग को सौंपी गयी प्री फिजिविलिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के बाद हिंदुस्तान जिंक द्वारा पारे की उपस्थिति स्वीकार की है। लेकिन इतने वर्षों से जो यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही थी उसके कारण चंदेरिया प्लांट से प्रति वर्ष निकल रहा Calomel यानि मरक्यूरस क्लोराइड आखिर कहाँ गया?
5. इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी द्वारा चंदेरिया प्लांट में लगाया गया Mercury Removal System (Calomel Process) सही काम कर रहा है? और वहाँ से पारे का शोधन सही प्रकार से किया जा रहा है?
6. इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड में पारे की एक निश्चित मात्रा 2.0 PPM को कायम रखा जाता है?
7. कंपनी द्वारा निकलने वाले सह उत्पाद Calomel (मरक्यूरस क्लोराइड) को किसे बेचा जाता है? प्रति वर्ष इसकी उत्पादकता क्या है?
8. कंपनी के अन्य प्लांटों देवारी, दरिबा में जहाँ यह सिस्टम नहीं लगा हुआ है वहाँ से निकलने वाला पारा आखिर कहाँ जा रहा है? प्रदूषण विभाग के उदयपुर और राजसमंद के अधिकारी अपनी रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी यह हरकत कंपनी के साथ उनकी मिलीभगत को नहीं दर्शाती?
9. कंपनी द्वारा इतने सालों में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया गया? किन किन उद्योगों-कारखानों को बेचा गया? जिन जिन कारखानों में जैसे सीमेंट, खाद एवं उर्वरक कारखानों में हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई की जाती है, वहाँ के उत्पादों में पारे की उपस्थिति/मात्रा का पता क्यों नहीं लगवाया जा रहा है?
10. स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से खेत खलिहानों, मनुष्यों, समुद्री जीवों को हो रहे जानोमाल के नुकसान की एक वजह क्या पारा नहीं है? क्या राज्य सरकार हिंदुस्तान जिंक लि. की खानों, स्मेल्टरों प्रोसेसिंग यूनिटों के आस-पास स्थित कुओं, तालाबों, नदी-नालों के पानी, वहाँ की आबो-हवा, स्थानीय निवासियों, जानवरों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर, पारे से हो रहे जानोमाल के नुकसान का आंकलन करवाएगी? आज दिनांक तक कंपनी द्वारा कितना मुआवजा/हर्जा-खर्चा इस पेटे दिया गया है?